

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक १५ फरवरी 2012

विषय:-ग्राम डाण्डानूरीवाला जनपद देहरादून में लोकायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड के निर्माण हेतु 1.00 है० भूमि निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

लोकायुक्त कार्यालय हेतु शासनादेश संख्या-554/XVIII(II)/2012-18(97)/2010 दिनांक 04 मार्च, 2011 द्वारा ग्राम लाडपुर परगना/ तहसील व जिला, देहरादून में आवंटित 0.296 है० भूमि से सम्बन्धित शासनादेश को निरस्त करते हुये आपके पत्र संख्या-341/डी०एल०आर०सी०-2011 दिनांक 17 दिसम्बर, 2011 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, ग्राम डाण्डानूरीवाला परगना परवादून तहसील व जिला देहरादून में लोकायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड के निर्माण हेतु कुल 1.00 है० भूमि सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड को, वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक-15.02.02 में निहित प्राविधानों एवं आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित खाता सं०-274 के खसरा संख्या-44 ज में अंकित 1.00 है० भूमि को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार, सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु, तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0संख्या-386/समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 5- प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।